संपादकीय

सुधार पर सुस्त रवैया

यह ठीक नहीं कि कई राज्य राशन प्रणाली में सुधार को लेकर अपेक्षित उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि भाजपा या उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्य भी सुस्ती का परिचय दें, लेकिन तथ्य यही है कि राशन की दुकानों को प्वाइंट ऑफ सेल यानी पॉस मशीनों से लैस करने में जो राज्य पीछे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और असम की भी गिनती की जा रही है। यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार लगातार इस पर जोर दे रही है कि सभी राज्य पात्र लोगों को ही राशन देना सुनिश्चित करने के लिए राशन की दुकानों में पॉस मशीनें लगाएं।

राज्य सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि राशन प्रणाली अभी भी खामियों से मुक्त नहीं हो सकी है। राशन प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का पता इससे चलता है कि जब राशन कार्डों की छानबीन का अभियान चला, तो करीब दो करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए। जाहिर है कि दो करोड़ लोगों के हिस्से का राशन अपात्र यानी भ्रष्ट तत्वों के पास जा रहा था।

आखिर जब पॉस मशीनें इस बंदरबांट पर लगाम लगाने में समर्थ हैं, तो फिर इसका क्या मतलब कि राशन दुकानों को इन मशीनों से लैस करने में आनाकानी का परिचय दिया जाए? यह आनाकानी भ्रष्टाचार के साथ-साथ एक तरह से संसाधनों के दुरुपयोग की भी अनदेखी है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रति खोखली प्रतिबद्धता का भी सूचक है।

यह गनीमत है कि उत्तर प्रदेश में तो राशन की दुकानों को पॉस मशीनों से लैस करने का काम धीमी गति से ही सही, कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार जहां का तहां नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल सरकार की भी है। हैरत नहीं कि ममता सरकार इस जरूरी काम की अनदेखी केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए कर रही हो।

जो भी हो, राज्यों के लिए उचित यही है कि वे जन-कल्याण की योजनाओं को सही तरह से लागू करने के प्रयासों को दलगत राजनीति से परे रखें। एक अनुमान के अनुसार फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जाने से ही करीब दस हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह इसलिए संभव हो सका, क्योंकि पॉस मशीनों को उपभोक्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने से पात्र लोगों की पहचान पुख्ता हो जाती है। यह प्रयोग इसी बात को रेखांकित करता है कि जन-कल्याण की योजनाओं को तकनीक के जरिए संचालित करके एक ओर जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है, वहीं वास्तविक जरूरतमंदों की सही तरह से मदद की जा सकती है।

मुश्किल यह है कि जब भी सरकारी योजनाओं को तकनीक से लैस करने की बात होती है तो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उसका विरोध शुरू हो जाता है। इसी प्रवृत्ति के चलते आधार कार्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। बेहतर है कि राज्य सरकारें राशन प्रणाली में सुधार लाने के मामले में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दें, क्योंकि इस प्रणाली में काफी कुछ सुधार के बाद भी उसे दुरुस्त करना शेष है और इसी वजह से उसके मूल्यांकन की एक योजना शुरू करनी पड़ रही है।

हमारी अहमियत समझ रहा चीन

भारत अब महाशक्ति बनने की राह पर है। वह पहले ही वैश्विक मसलों में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ, समृद्ध और पर्यावरणीय रूप से सतत भविष्य निर्माण की रूपरेखा बनाने में उसकी राय को तवज्जो दी जाती है। साथ ही भारत अब उन औद्योगिक देशों में शामिल हो गया है जो बड़े पैमाने पर संसाधनों का दोहन कर रहा है। भौगोलिक आकार, भू-रणनीतिक स्थिति, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सशक्त होते सैन्य बल के साथ ही भारत के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को अमेरिका सहित दुनिया के अधिकांश देशों ने स्वीकार किया है। आज ताकतवर देशों का प्रत्येक गुट भारत को अपनी ओर आकर्षित करने की फिराक में लगा है, क्योंकि उसके साथ से दुनिया में शक्ति के संतुलन का पलड़ा उस गुट के पक्ष में झुक सकता है।

दूसरी ओर चीन वैश्विक मामलों में भारत को बराबर का साझेदार मानने को लेकर हिचकता है। पिछले कुछ समय से बीजिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धैर्य की परीक्षा के लिए भारत के प्रति %कभी गर्म तो कभी नर्म वाली नीति अख्तियार करता आया है। यह बात अब छिपी नहीं रह गई है कि चीन भारत पर शिकंजा कसने के लिए उसके आसपड़ोस में %मोतियों की माला के रूप में सामरिक घेरेबंदी करने में जुटा है। इसी तरह वन बेल्ट, वन रोड यानी ओबोर और मेरीटाइम सिल्क रूट भी चीन के बढ़ते भू-राजनीतिक रुतबे का प्रतीक है। बीजिंग दुनियाभर में बंदरगाहों और एयरफील्ड में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। साथ ही अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के साथ ही अपने व्यापारिक साझेदार देशों के राजनीतिक-सैन्य नेतृत्व को प्रभावित करने में भी जुटा है। इस पर बीजिंग का यही कहना है कि चीनी नौसेना की बढ़ती ताकत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही है जिसका एकमेव मकसद अपने क्षेत्रीय व्यापारिक हितों को रक्षा करना है, लेकिन चीनी गतिविधियों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही चीन कूटनयिक एवं मीडिया सूत्रों के माध्यम से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी और क्षेत्रीय सहयोग के लिए बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम) से जुड़ने के लिए भारत को लुभाने की भी यदा-कदा कोशिशें भी करता है, क्योंकि केवल भारत के पास ही वह क्षमता है जो इस क्षेत्र में चीनी जहाजों के बेड़े को अपने दखल से प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ चीनी सरकारी मीडिया भी गाहे-बगाहे भारत को धमकाता रहता है कि अगर भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन के संबंधों में दखल दिया तो बीजिंग इस पर पलटवार जरूर करेगा। उसका आरोप है कि भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर को अपनी थाती समझता है और भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव से इस क्षेत्र में चीनी परियोजनाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। चीन का कहना है कि हिंद महासागर भारत का नहीं है तो भारत भी इस पर यही जवाब देता है कि दक्षिण चीन सागर भी चीन की बपौती नहीं। हालांकि भारत के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने के लिए बीजिंग बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है।

भारत ने भी चीन की इस चाल का कुशलता से जवाब दिया है। चीन की 14 देशों के साथ कुल 22,147 किलोमीटर लंबी सीमा है और आठ देश उसके सामुद्रिक पड़ोसी हैं। इनमें पाकिस्तान को छोड़कर अधिकांश देशों के साथ उसके रिश्ते असहज हैं। फिर जापान, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम के साथ जमीन एवं समुद्री सीमा विवाद भी हैं। आसियान देश भी चीनी प्रभुत्व को लेकर खासे खिन्न हैं। वहीं भारत ने चीन के पड़ोसियों विशेषकर दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम से रणनीतिक गठजोड़ कर अपनी स्थिति बेहतर की है। चीन की काट निकालने के लिए इस साल गणतंत्र दिवस पर आसियान नेताओं को बुलाना मोदी की दक्षिण-पूर्व एशियाई नीति का अहम हिस्सा था। भारत और वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी तेजी से परवान चढ़ी है। इस प्रकार चीन को काबू में रखने की मोदी की रणनीति काफी हद तक कारगर होती दिख रही है। वहीं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चतुष्कोणीय साझेदारी की बात निर्णायक पड़ाव पर है। चीन के करीबी पाकिस्तान को अलग-थलग करने की भारतीय रणनीति भी रंग ला रही है। मोदी की विदेश नीति बहुत ही व्यावहारिक है। उन्होंने दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ आत्मीय रिश्ते बनाए हैं। ओबोर के जवाब में कहीं अधिक लोकहितैषी एशिया-अफ्रीका वृद्धि गलियारा और बीजिंग के बीसीआईएम के जवाब में बिम्सेटक को कूटनीति का मास्टरस्ट्रोक कहा जा सकता है। इसराइल और अरब देशों में सऊदी अरब एवं ईरान के साथ बराबर संतुलन से रिश्ते साधे जा रहे हैं। स्टॉकहोम में सफलतापूर्वक नॉर्डिक सम्मेलन संपन्न् हुआ। रूस और अमेरिका की तनातनी में भी अपने हित सुरक्षित रखे। अपनी इन खूबियों के चलते ही मोदी अधिकांश विश्व नेताओं को लुभाते हैं। उन्होंने डोकलाम सैन्य गतिरोध को भी बखूबी संभाला, मालाबार युद्धाभ्यास भी सही दिशा में आगे बढ़ा, वायुसेना के हालिया युद्धाभ्यास %गगन शक्ति में आसमान में हमारी मारक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारत-तिब्बत सीमा पर सुरक्षाबलों की समुचित तैनाती और उत्तरी सीमा पर सेना और उसके साजोसामान को समुन्नत बनाने के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों की खरीद ने भी चीन को भारत के बढ़ते कद का एहसास कराया है कि उसकी सैन्य शक्ति की और ज्यादा अनदेखी नहीं की जा सकती।

फिर मौजूदा भू-राजनीतिक कारकों की बारी आती है। चीन के साथ ट्रेड वार पर आमादा अमेरिकी राष्ट्रपति को देखते हुए भी चीन को भारत के साथ की अहमियत मालूम पड़ी होगी। यही वे कारण हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए जिनपिंग ने मोदी को दो दिन की अनौपचारिक वार्ता के लिए वुहान आमंत्रित किया।

वुहान में कोई औपचारिक एजेंडा भले ही नहीं था, लेकिन इसने भविष्य के लिए जरूर कुछ मुद्दे तय कर दिए हैं। दोनों नेता अपनी सेनाओं के बीच बेहतर संवाद पर सहमत हुए हैं, ताकि सीमा पर हालात सहज रहें। सीमा विवाद के मामले में उन्होंने विशेष प्रतिनिधियों पर भरोसा जताया है जो उचित, पारदर्शी और परस्पर स्वीकार्य समझौते को आकार देंगे। इस बीच सरहद पर शांति के महत्व को भी भलीभांति समझा गया है। चीनी मीडिया इस पर खासा उत्साहित जरूर रहा, लेकिन बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद अभी भी कुछ पेंच फंसे हुए हैं। मसलन सीमा विवाद, हिंद महासागर में धींगामुश्ती और जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर पर आपत्ति जैसे मसलों पर तनातनी का भाव है। मोदी ने संकेत दिए हैं कि सीपीईसी को लेकर भारत की आपत्ति यही है कि वह कश्मीर के विवादित क्षेत्र से गुजर रहा है। पाकिस्तानी आतंकियों को चीन की शह पर भी नई दिल्ली नाराज है। वहीं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की चौकड़ी पर भी चीन अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। दलाई लामा और अन्य निर्वासित तिब्बती नेताओं की भारत में मौजूदगी पर भी चीन आशंकित है।

वुहान से भले ही कोई प्रत्यक्ष परिणाम न निकला हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह सम्मेलन विश्व स्तर पर भारत की धमक का मंच बना, जहां चीन ने भी इस पहलू को विनम्रता के साथ स्वीकार किया।

कैंसर की तरह फैलता अवैध निर्माण

हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक होटल मालिक ने अवैध निर्माण हटाने आई सहायक नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला की जिस तरह गोली मारकर हत्या कर दी, वह अपराध की सामान्य घटना नहीं है। शैलबाला को गोली मारने वाले होटल मालिक ने पहले ले-देकर अपने अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश की। जब वह नाकाम रहा तो उसने पुलिस की मौजूदगी में सहायक नगर नियोजन अधिकारी की हत्या कर दी। यह घटना इसलिए कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रही थी। इस महिला अधिकारी की शहादत के बावजूद इसके आसार कम हैं कि देश में कैंसर की तरह बढ़ते अवैध निर्माण की समस्या पर नौकरशाहों और नेताओं की नींद खुलेगी। आज देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, चाहे वह गांव हो या देश की राजधानी दिल्ली, जहां किसी तरह का अवैध या अनियोजित निर्माण न हुआ हो। पहले सरकारी जमीनें ही अवैध कब्जे और निर्माण की भेंट चढ़ती थीं, लेकिन अब निजी जमीनों पर भी अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

सरकारी अथवा गैरसरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और अनियोजित विकास को रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों, प्रशासन और अंततः राज्य सरकारों की है। यदा-कदा स्थानीय निकायों अथवा जिला प्रशासन के अधिकारी स्थायी-अस्थायी अवैध निर्माण को बुलडोजर लेकर गिरा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पहले वाली स्थिति हो जाती है। कई बार तो दो-तीन दिन में ही अतिक्रमणकारी लौट आते हैं या फिर रोका गया अवैध निर्माण पुनः शुरू हो जाता है। इसी तरह सरकारी जमीनों से हटाई गई झुग्गियां फिर से खड़ी होने लगती हैं। कभी-कभी तो इन झुग्गियों को बसाने के लिए नेतागीरी भी होने लगती है। धीरे-धीरे ये झुग्गियां बस्ती का रूप ले लेती हैं और फिर वहां नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की मांग होने लगती है। जल्द ही ऐसी बस्तियों को नियमित करने की जरूरत जताई जाने लगती है, क्योंकि इन बस्तियों में रहने वाले किसी नेता के वोटर बन जाते हैं। देरसबेर इन बस्तियों को नियमित भी कर दिया जाता है, जबकि वे बेतरतीब और अनियोजित विकास का नमूना होती हैं।

झुग्गी बस्तियों को नियमित करते समय न तो नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता की चिंता की जाती है और न ही पर्यावरण की। इसके चलते गंदगी, प्रदूषण और यातायात जाम जैसी समस्याएं सिर उठा लेती हैं। आज शहरी जीवन कहीं अधिक समस्याओं से घिरा और सेहत के लिए हानिकारक होता जा रहा है। शहरी जीवन का चुनौतीपूर्ण होते जाना खतरे की घंटी है, लेकिन लगता है कि किसी को भी यह घंटी सुनाई नहीं दे रही है। समझना कठिन है कि नगर नियोजन का काम देखने वाले अथवा मास्टर प्लान बनाने और उसे लागू करने वाले क्या सोचकर अनियोजित विकास और अवैध निर्माण की अनदेखी करते हैं? भारत एक विकासशील देश है और यह माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दशकों में देश की करीब आधी आबादी शहरों में निवास करेगी। इसे देखते हुए जब शहरीकरण के मानकों पर सख्ती से पालन होना चाहिए तब ठीक इसके उलट हो रहा है। सड़कें, फुटपाथ और पार्क अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं, फिर भी कोई नहीं चेतता। अगर कभी कोई चेतता है तो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यावसायिक स्थलों की सीलिंग का सिलसिला इसी कारण कायम है, क्योंकि नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं ने नियोजित विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि कई एनजीओ एवं अन्य नागरिक संगठन पर्यावरण बचाने को लेकर सक्रिय हैं और वे अनियोजित विकास के मसले उठाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी और नेता मुश्किल से ही उनकी सुनते हैं। वे तभी हरकत में आते हैं, जब अदालत कोई आदेश देती है। इस पर भी उनकी पहली कोशिश अदालती आदेश की खानापूरी करने की अधिक होती है।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्प्लेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, एच-47, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया।
फोन-26568477, 26409779.
E : alpaviram1@yahoo.com

बार-बार नाकामी के बावजूद बड़े ख्वाब

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल के जवाब में खुद को वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करते हुए यही दर्शाया कि उनकी राजनीतिक समझ-बूझ चाहे जैसी भी हो, लेकिन साहस की उनमें कोई कमी नहीं है।

वैसे राहुल को मुख्यतः दो कारणों से खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने से बचना चाहिए था। पहला कारण तो यह कि कांग्रेस की लगातार यही कोशिश रही है कि वर्ष 2019 के आम चुनाव को राष्ट्रपति शैली के चुनाव में तब्दील होने से रोका जाए। यदि मोदी बनाम राहुल की स्थिति बनती है, तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान तय है। राहुल गांधी एक वंशवादी पैराशूटर हैं, जिन्होंने अपने तकरीबन डेढ़ दशक के सियासी जीवन में न तो अब तक कोई चुनावी सफलता हासिल की है और ना ही किसी मंत्रालय का प्रभार संभाला है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी एक जमीन से जुड़े ओबीसी नेता हैं, जिनका पूरा जीवन राजनीति में गुजरा है। वे लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर वर्ष 2014 में अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में लेकर आए। जाहिर है मोदी के मुकाबले राहुल कहीं नहीं ठहरते।

दूसरा कारण, गैरकांग्रेसी विपक्ष ने अब तक ऐसी कोई मंशा नहीं दर्शाई है कि वह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर स्वीकार करने को तैयार है। बल्कि विपक्षी दलों की ओर से तो ऐसे भी कोई संकेत नहीं कि वे चुनाव-पूर्व गठबंधन में कांग्रेस को नेतृत्वकारी भूमिका देने के लिए भी तैयार हैं। कुछ समय पूर्व तृणमूल कांग्रेस ने संभावित विपक्षी गठबंधन के नेता के लिए जो मानदंड निर्धारित किए थे, राहुल उनमें से एक पर भी खरे नहीं उतरते। राहुल गांधी का कहना है कि यदि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है तो वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह कहते वक्त शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि क्षेत्रीय दल तो उनके साथ आ ही जाएंगे। लेकिन यह न भूलें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जूनियर साझेदार की भूमिका में होगी, जिनमें लोकसभा सीटों की बड़ी संख्या है। ऐसे में राहुल गांधी का यह नेतृत्व संबंधी सहज आकलन क्षेत्रीय ताकतों को खफा कर देगा, जबकि उन्हें इस वक्त इनके समर्थन की बेहद जरूरत है।

एक बात और, राहुल गांधी खुद को अब तक ऐसे राजनेता के तौर पर पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके पास स्पष्ट विजन हो। हां, वे आर्थिक मोर्चे पर एनडीए सरकार की तमाम नाकामियों, मसलन बेरोजगारी, बैंकों का बढ़ता एनपीए, घटती विकास दर, कृषि संकट, तेल की बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार और लुढ़कता रुपया इत्यादि को उचित रेखांकित करते हैं, लेकिन उनके पास इनमें से एक भी समस्या के समाधान की योजना नहीं है। आज तक वे हमारे समक्ष एक भी बड़ा दमदार आइडिया पेश नहीं कर सके हैं।

दूसरी ओर, मोदी के पास नए-नए आइडियाज की भरमार है। स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, फसल बीमा, किसानों की आय दोगुनी करना इत्यादि के भले ही अब तक वांछित नतीजे न मिल सके हों, लेकिन मोदी ने कम से कम नए-नए विचार तो पेश किए, जो देश में पिछले चौथाई दशक से कायम यथास्थितिवादी मानसिकता को चुनौती पेश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदम उठाते हुए यह भी दर्शाया कि वे बड़े दांव खेलने के लिए तैयार हैं, चाहे उन्हें हार मिले या जीत!

राहुल को यह बात समझनी चाहिए कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी थाल में सजाकर नहीं मिलने वाली, जैसी कि उनके पिता को मिल गई थी। उन्हें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, अपने पूर्वजों से भी कहीं ज्यादा सख्त लड़ाई। हां, इस मामले में जवाहरलाल नेहरू अपवाद हो सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से बेहद सख्त संघर्ष किया था। राहुल डेढ़ दशक से राजनीति में हैं, पांच साल तक पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं और पांच महीने से अध्यक्ष हैं, लेकिन अब भी उनके खाते में कोई चुनावी सफलता दर्ज नहीं है। आलम यह है कि कांग्रेस आज सिद्धारमैया और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों पर पहले के मुकाबले कहीं अधिक निर्भर है। ऐसे में मोदी जब यह तंज कसते हैं कि कांग्रेस तो %पीपीपी (पंजाब, पुडुचेरी और परिवार) पार्टी बनकर रह जाएगी, तो उनका निशाना राहुल ही होते हैं।

लिहाजा, राहुल गांधी को न सिर्फ चुनाव जीतने होंगे, बल्कि देश के आम लोगों का भरोसा भी जीतना होगा। उसके बाद ही वे सहयोगियों में अपनी स्वीकार्यता की उम्मीद कर सकते हैं और तभी वे पीएम पद के एक गंभीर दावेदार बन सकते हैं। राहुल के वक्तव्य से कांग्रेस के उन नेताओं को भी निराशा हुई होगी, जो उम्मीद पाले बैठे थे कि यदि कांग्रेस 2019 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो उन्हीं में से किसी एक को पीएम का पद आउटसोर्स किया जा सकता है (बशर्ते सहयोगी दल तैयार हों)।

राहुल गांधी ने अपने सियासी करियर में एक दशक (2004-2014) तक अपने काम को गंभीरता से नहीं लिया। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के बजाय अपने मित्रों के साथ ज्यादा वक्त बिताते नजर आते थे। लेकिन वर्ष 2014 के आम चुनाव में मिली शर्मनाक हार संभवतः उनके जीवन में निर्णायक मोड़ लेकर आई। वर्ष 2013 में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा था कि %सत्ता जहर है, लेकिन जब उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 44 सीटों तक सिमट गई, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि सत्ता तो वास्तव में पार्टी के लिए संजीवनी है। पार्टी के पराभव के चलते हिमंत बिस्व सरमा, एसएम कृष्णा और रीता बहुगुणा जोशी जैसे कई दिग्गज नेताओं ने पाला बदलते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं राव इंद्रजीत सिंह और होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह जैसे कुछ नेता लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में चले गए और अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे।

यह सही है कि राहुल गांधी ने अपनी %पप्पू छवि को बदलने के लिए खूब मेहनत की। लेकिन वह प्रधानमंत्री पर निजी हमले करने से खुद को रोक नहीं पाते, जो उनके लिए आत्मघाती साबित होता है। उनका यह बचकाना कथन कि %यदि मैं बोलूंगा, तो प्रधानमंत्री 15 मिनट भी मेरे सामने बैठ नहीं पाएंगे, मोदी के लिए उनके कर्नाटक चुनाव प्रचार अभियान में बहुत उपयोगी साबित हुआ। मोदी ने इसे आधार बनाते हुए राहुल के वंशवादी मूल का राग छेड़ दिया और कहा कि वे (राहुल) %नामदार हैं और हम %कामदार लोग हैं। हम उनके समक्ष बैठ भी कैसे सकते हैं।

राहुल के लिए मुख्य चुनौती जनता को यह दिखाना है कि उनके पास उपनाम के अलावा भी बहुत कुछ है और सिर्फ नामदार नहीं, बल्कि कामदार भी हैं। वह दौर अब नहीं रहा, जब देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। अब तो वंशवादियों को भी मैदान में खुद को साबित करना होगा। पप्पू पास हुए बिना प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।

चीन के आर्थिक गलियारे की काट

बहुत दिन नहीं हुए जब चीन से एक रेलगाड़ी 12 हजार किमी का सफर तय करके इंग्लैंड पहुंची। इस ट्रेन में चीनी फैक्ट्रियों में तैयार कपड़े और अन्य सामान था। इस ट्रेन का पहुंचना चीन द्वारा बनाई जा रही बेल्ट रोड का ट्रेलर था, जो उसकी महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। चीन के माल को यूरोप और अफ्रीका में पहुंचाने के लिए 65 देशों के बीच से एक गलियारे का निर्माण होगा, जो सड़क और रेल यातायात को सुलभ बनाएगा। बेल्ट रोड बनने के बाद चीन के माल को यूरोप पहुंचाना आसान हो जाएगा और इससे चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा।

वर्तमान में अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रिकल स्विच जैसी वस्तुएं यूरोप को आपूर्ति की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका का माल सस्ता पड़ रहा है। वहीं %बेल्ट रोड बनने के बाद चीन में बने इलेक्ट्रिकल स्विच सस्ते पड़ेंगे। तब यूरोपीय ग्राहक अमेरिका के स्थान पर चीनी माल खरीदने को तरजीह देंगे। इसलिए बेल्ट रोड का असल मुद्दा चीन बनाम अमेरिका का है। यूरोप में अमेरिकी वर्चस्व को चीन बेल्ट रोड के माध्यम से चुनौती दे रहा है। इस तरह चीन विश्व अर्थव्यवस्था का नया रूप स्थापित करने में लगा हुआ है। इस विषय को विश्व अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर के तहत देखना चाहिए।

वर्तमान में अमेरिका, जापान और यूरोप के विकसित देशों में विश्व की 25 प्रतिशत आबादी रहती है, जबकि इन देशों के पास दुनिया की 75 प्रतिशत आय है। दूसरी तरफ चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों में विश्व की 75 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन इन देशों के पास विश्व की केवल 25 प्रतिशत आय है। अगर बेल्ट रोड सफल होता है तो विश्व अर्थव्यवस्था का यह असंतुलन टूटेगा। विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की आय का हिस्सा बढ़ेगा और अमेरिका का हिस्सा घटेगा। इसीलिए अमेरिका का प्रयास है कि विश्व अर्थव्यवस्था के इस वर्तमान असंतुलन को बनाए रखा जाए। भारत के सामने संकट यह है कि बेल्ट रोड का एक हिस्सा चीन से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से होकर अरब सागर के ग्वादर पोर्ट तक पहुंच रहा है। बेल्ट रोड के इस हिस्से से चीन को अपना माल अफ्रीका तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। भारत की आपत्ति है कि यह रोड पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से गुजरता है और इससे भारत की संप्रभुता को चुनौती मिलती है। इसीलिए भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर बेल्ट रोड का विरोध किया है। इसमें संदेह है कि भारत और अमेरिका का यह विरोध सफल होगा। इसका कारण यह है कि चीन ने बेल्ट रोड बनाने के लिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं से मदद नहीं ली है। चीन के सरकारी बैंक विश्व पूंजी बाजार में निजी निवेशकों से कर्ज ले रहे हैं और इस रकम को द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से उन 65 देशों को दे रहे हैं जिनके बीच से बेल्ट रोड गुजरनी है। ऐसे में अमेरिका और भारत शोर मचा सकते हैं, लेकिन बेल्ट रोड पर कोई अड़ंगा नही लगा सकते, क्योंकि वे इसके दायरे से बाहर हैं। भारत के सामने दो परस्पर विरोधी मुद्दे हैं। एक तरफ विश्व अर्थव्यवस्था का असंतुलन है। इसे प्रमुखता दें तो भारत को चीन के साथ मिलकर बेल्ट रोड में सहयोग देना चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर आय का असंतुलन दूर हो और भारत एवं चीन का विश्व अर्थव्यवस्था में हिस्सा बढ़े। दूसरी ओर भारत यदि संप्रभुता के मुद्दे को प्रमुखता देता है तो उसे इसका विरोध करना होगा। मेरे आकलन में भारत को 70 साल से चले आ रहे कश्मीर विवाद के चलते विश्व अर्थव्यवस्था के वर्तमान असंतुलन को बनाए रखने के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। कश्मीर विवाद को किनारे रखकर या कुछ हल निकालकर विश्व अर्थव्यवस्था के असंतुलन के मुख्य मुद्दे पर कार्य करना चाहिए। बेल्ट रोड के माध्यम से चीन मुख्यत अपनी फैक्ट्रियों में उत्पादित माल को यूरोप पहुंचाना चाहता है। विश्व अर्थव्यवस्था में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा क्रमशः घटता जा रहा है। वर्तमान में विकसित देशों में सेवाओं का हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत, उत्पादित माल का 9 प्रतिशत और कृषि का एक प्रतिशत है। बेल्ट रोड के माध्यम से चीन उत्पादित माल के नौ प्रतिशत हिस्से में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत के सामने चुनौती है कि विश्व आय के 90 प्रतिशत सेवा क्षेत्र के हिस्से में अपनी पैठ बनाए। भारत को एक महत्वाकांक्षी ग्लोबल सर्विसेस पाथवे योजना बनानी चाहिए जिसके माध्यम से सेवाओं जैसे कंप्यूटर गेम्स, सॉफ्टवेयर, यातायात, अंतरिक्ष प्रक्षेपण आदि का वैश्विक बाजार विकसित हो।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

मंडल रेल प्रबंधक, इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है- ई-निविदा सूचना सं0 2018-19 : 79 : कार्य का नाम व स्थान : (Hiring of Vehicle) Zone 4:- Hiring of truck multi utility vehicle & tractor for leading of P.Way materials and different other purpose in the section of ADEN/Barmer for year 2018-19 & 2019-20. अनुमानित लागत रुपये : Rs. 1,26,82,865.56 बयाने की राशि रुपये : Rs. 2,13,420.00 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि : 15.06.2018 वेबसाईट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है : www.ireps.gov.in 537-AD/18

हमें /NWRailways पर फॉलो करें